उपक्रम तथा अन्य संगठन

रेल मंत्रालय के अंतर्गत कुल 16 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और अन्य संगठन काम कर रहे हैं, जो निम्नलिखित हैं:-

क्र. सं.	नाम	निगमित/शुरू किए जाने का वर्ष	मुख्य कार्यक्षेत्र
1	राइट्स	1974	भारत और भारत से बाहर रेलवे और अन्य क्षेत्रों/ इंडस्ट्रियों से संबंधित सभी प्रकार की परियोजनाओं/ प्रणालियों के विकास के लिए डिजाइन तैयार करना, स्थापित करने, प्रदान करने, परिचालन करने, अनुरक्षण और निष्पादित इंजीनियरिंग, तकनीकी एवं परामर्श सेवाएं देना।
2	इरकॉन	1976	भारत और विदेश में रेलवे, पुलों, सड़कों, राजमार्गों, औद्योगिक और रिहायशी कॉम्पलेक्सों,एयरपोर्टों आदि जैसे अवसंरचना के विभिन्न क्षेत्रों में टर्नकी अथवा अन्यथा के आधार पर निर्माण गतिविधियों को शुरू करना।
3	क्रिस	1986	नए उत्पादों या सेवाओं के निर्माण के लिए और विवेकपूर्ण संव्यवहार और प्रौद्योगिकियों को क्रियान्वित करने के लिए प्रौद्योगिकी पहलकदमियों की अवधारणा को साकार करने के लिए साझीदार के रूप में भारतीय रेल को परामर्श और आईटी सेवाएं मुहैया कराना।
4	आईआरएफसी	1986	भारतीय रेल के योजना परिव्यय को आंशिक वित्तपोषण मुहैया कराने के लिए बाजार से धन एकत्रित करना।
5	कॉनकोर	1988	भारत के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू कंटेनर वाले कार्गो और व्यापार के लिए बहु-आयामी लॉजिस्टिक सहायता मुहैया कराना।

6	केआरसीएल	1990	रेल लाइनों के निर्माण और परिचालन, ऊपरी सड़क पुलों और रेल लाइन परियोजनाओं के निर्माण के लिए।
7	आरसीआईएल (रेलटेल)	2000	ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित ब्रॉडबैंड दूरसंचार और मल्टीमीडिया नेटवर्क का देशव्यापी निर्माण करने के लिए भारतीय रेल के पास उपलब्ध अधिशेष दूर-संचार क्षमता और मार्गाधिकार का उपयोग करने के लिए।
8	आईआरसीटीसी	2001	रेलवे की खान-पान और पर्यटन गतिविधियों को शुरू करने के लिए। अपनी वेबसाइट द्वारा इंटरनेट टिकटिंग की सुविधा भी प्रदान करता है।
9	पीआरसीएल	2001	सुरेंद्रनगर-राजुला-पीपावाव पोर्ट आमान परिवर्तन योजना और गुजरात में नई लाइन परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए।
10	आरवीएनएल	2003	रेल अवसंरचना क्षमता का निर्माण और आवर्धन करने के लिए, मुख्यत: बहुपक्षीय/द्विपक्षीय वित्तपोषण एजेंसियों के माध्यम से और परियोजनाओं के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए घरेलू बाजार से संसाधनों को जुटाने के लिए।
11	आरएलडीए	2005	भारतीय रेल के लिए गैर-दरसूची उपायों द्वारा राजस्व सृजित करने के उद्देश्य से वाणिज्यिक प्रयोग के लिए खाली पड़ी रेल भूमि के विकास हेतु।
12	डीएफसीसी आईएल	2006	गलियारों पर मालगाड़ियों के संचालन के लिए समर्पित रेल माल यातायात गलियारों (डीएफसी) की योजना तैयार करने और निर्माण करने के लिए।
13	एमआरवीसी	1999	मुंबई महानगर क्षेत्र में रेल परियोजनाओं की योजना बनाने और क्रियान्वयन करने के लिए।
14	बीडब्ल्यूईएल	1978 (रेल मंत्रालय में 2008 से)	माल डिब्बों के निर्माण और ढांचागत फैब्रीकेशन कार्यों के लिए।
15	बीएससीएल	1976 (रेल मंत्रालय में 2010 से)	रेलवे चल स्टॉक के निर्माण के लिए।
16	बीसीएल	1976 (रेल मंत्रालय में 2010 से)	माल डिब्बों के निर्माण, ढांचागत फैब्रीकेशन कार्यों और ईओटी क्रेनों के विनिर्माण, रिट्रोफिटिंग के लिए।

रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड (राइट्स):

राइट्स, रेल मंत्रालय के तत्वावधान में भारत सरकार की अनुसूची 'ए' की एक मिनी रत्न कैटेगरी-I का एक आईएसओ:9001-2008 प्रमाणित बहु-आयामी कुल परिवहन इंजीनियरिंग और प्रबंधन परामर्श संगठन है। इसे अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, मिडल ईस्ट और लैटिन अमेरिका में 60 देशों के परिचालनिक अनुभव सहित कई राष्ट्रीय सरकारों और अन्य शीर्ष संगठनों के एक प्रमुख परामर्शदाता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त है। यह मौजूदा और नई अवसंरचनात्मक विकास परियोजनाओं की कुशलतापूर्वक कार्यप्रणाली के लिए पुनर्स्थापन, विकास, आधुनिकीकरण और इष्टतम समाधान के लिए संस्थागत प्रबंधन एवं तकनीकी समर्थन के लिए पूरी तरह सुसज्जित हैं।

राइट्स अवसंरचना क्षेत्र और परिवहन के सभी साधनों जैसे रेलवे, राजमार्गों, पत्तनों, जलमार्गों, एयरपोर्टों, रोपवे, शहरी परिवहन, शहरी योजना, कंटेनर डिपुओं, संस्थागत भवन, पॉवर ट्रांसमिशन और ग्रामीण विद्युतीकरण आदि के लिए एक ही छत के नीचे व्यापक सेवाएं प्रदान करता है और उपयोगकर्ता संगठनों को प्रौद्योगिकी के अंतरण में विश्वास रखता है।

व्यवसाय संबंधी कार्यकलाप:

विगत में किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्नानुसार हैं :

विदेशों में :

- 20 डेमू ट्रेनसेटों, बड़ी लाइन 2300 एचपी डीजल इंजन, मशीनरी और संयंत्र, इंजन के कलपुर्जों और यूनिट एक्सचेंज मदों की आपूर्ति, तीन स्थानों पर डेमू के अनुरक्षण सुविधाओं का निर्माण करना, श्रीलंका सरकार के लिए भारत में 600 श्रीलंका कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना।
- बांग्लादेश रेलवे को नए बड़ी लाइन डीज़ल इंजनों की आपूर्ति।
- इन-सर्विस मीटर लाइन इंजनों, इन-सर्विस मीटर लाइन एसी सवारी डिब्बों, 250 मीटर

लाइन डिब्बों, इंजनों के कलपुर्जों, डंपर ट्रक जैसे उपकरण, म्यांमार रेलवे के लिए रेल गैंग कारें और रोड क्रेन का विकास। राइट्स म्यांमार में त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजनाओं को भी निष्पादित कर रहा है।

- कलेतवा से भारत-म्यांमार सीमा तक सड़क के लिए व्यवहार्यता और डीपीआर।
- इंडो-नेपाल सीमा पर रेल अवसंरचना के विकास के लिए परामर्श। इसके अलावा, मेची-महाकाली और पोखरा-काठमांडु नई रेलवे लाइन का व्यवहार्यता अध्ययन।
- कामेम्बे और गिसेनाई एयरपोर्ट रवांडा के विस्तार के लिए व्यवहार्यता अध्ययन और डिजाइन।
- गेबोन सरकार के लिए मयुंबा नई स्टैंडर्ड गेज रेल लाइन हेतु व्यवहार्यता अध्ययन।

भारत में :

- आरसीएफ-कपूरथला के लिए बज-बज/कोलकाता में फिएट निर्माण इकाई की स्थापना।
- रेल पहिया कारखाना, बंगलौर में पहियों के लिए डिजाइन और टेस्टिंग केंद्र की स्थापना।
- डीएफसीसीआईएल के लिए 4 नए समर्पित रेल फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसी) (6000 से अधिक किलोमीटर की दूरी) का प्रारंभिक इंजीनियरिंग एवं यातायात सर्वेक्षण (पीईटीएस) अध्ययन।
- पड़ोसी देशों की सीमाओं पर यात्री और कार्गो संचलन के लिए विश्वस्तरीय सुविधा के साथ एकीकृत जांच चौकियां।

वित्तीय निष्पादन:

पिछले दो वर्षों के दौरान राइट्स का तुलनात्मक वित्तीय निष्पादन इस प्रकार है:-

		(₹ करोड़ में)
	2011-12	**2012-13**
कुल टर्नओवर	934	**1,076**
शुद्ध लाभ	164	**245**
शुद्ध मूल्य	1,001	**1,195**

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन):

इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) रेल मंत्रालय के तत्वावधान में देश और विदेश में रेल नेटवर्क के निर्माण एवं विकास के मुख्य उद्देश्य से वर्ष 1976 में निगमित एक 'मिनी रत्न' कैटेगरी-I और अनुसूची 'ए' सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। अपनी तीन दशकों से अधिक की यात्रा में कंपनी ने राजमार्गों, सुरंगों, पुलों, फ्लाईओवरों, ऊपरी सड़क पुलों, एयरपोर्ट हैंगर एवं हवाई पट्टियों, मेट्रो रेल और भवन, ईएचवी ट्रांसमिशन लाइन एवं ग्रिड उप-स्टेशन, औद्योगिक विद्युतीकरण, सिगनल एवं दूरसंचार प्रणालियों आदि जैसे अन्य परिवहन और अवसंरचना क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों में विविधता हासिल की है। कंपनी ने अभी तक भारत में राष्ट्रीय महत्व के लगभग 296 अवसंरचनात्मक परियोजनाओं और 20 से भी अधिक देशों में 100 से भी अधिक परियोजनाओं को पूरा किया है। यह अमेरिका के इंजीनियरिंग न्यूज रिकार्ड (ईएनआर) के अनुसार शीर्ष 225 अंतर्राष्ट्रीय ठेकेदारों की सूची में स्थान बनाने वाली चार भारतीय कंपनियों में से एक है। हाल ही में कंपनी त्वरित दर से बढ़ रही है और सभी मापदंडों पर शानदार और बहुत ही वांछनीय परिणाम प्रदर्शित कर रही है. उनमें से कुछ को नीचे दिया गया है:

वित्तीय निष्पादन:

वर्ष के दौरान, समझौता ज्ञापन के लक्ष्य को पीछे छोड़ते हुए इरकॉन ने ₹4,232 करोड़ की अपनी उच्चतम परिचालन आय हासिल की. टैक्स से पहले लाभ (पीबीटी) भी अभी तक का अपने उच्चतम ₹1,015 करोड़ पर था जो 2011-12 में हासिल किए गए लाभ से 69% अधिक है. कर के बाद का लाभ भी 55% बढ़ कर ₹470 करोड़ से ₹730 करोड़ हो गया है. इस अवधि के दौरान, शुद्ध विदेशी मुद्रा जो ₹887 करोड़ है, लगभग दुगनी हो गई है. कंपनी का पीबीटी, जो वर्ष 2007-08 में ₹160.46 करोड़ था, में पिछले पांच वर्षों के दौरान 44.61% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ 2012-13 में ₹1,015 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर तक की वृद्धि हुई है।

विदेशी परियोजनाओं पर निष्पादन:

इरकॉन, दक्षिण-दक्षिण सहयोग की भावना के साथ, उनके ढांचागत विकास की कहानी

में एशियाई और अफ्रीकी देशों में सक्रिय रूप से लगी हुई है. इसकी पहचान इस तथ्य से हुई है कि वर्ष 2012–13 में इसकी ₹4,232 करोड़ की सबसे उच्चतम परिचालनिक आय का 47% विदेशी परियोजनाओं से है. कंपनी के व्यवसाय का विदेशी शेयर पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान 11% की तुलना में पिछले पांच वर्षों में लगभग 50% के स्तर तक बढ़ गया है. इरकॉन पिछले पांच वर्षों के दौरान ₹2,117 करोड़ की पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ निर्माण कंपनियों में से एक है.

कंपनी द्वारा विदेशी में पूरी की गई परियोजनाओं में मलेशिया में एक अरब अमरीकी डालर से अधिक के मूल्य वाली मेगा परियोजना शामिल हैं, जो विदेश में किसी भारतीय कंपनी द्वारा पूरी की गई सबसे बड़ी परिवहन परियोजना है. इसके अलावा, कंपनी इस समय, श्रीलंका और अल्जीरिया में बहुत अधिक महत्वाकांक्षा वाली परियोजनाओं के निष्पादन में लगी हुई है. इरकॉन के नेतृत्व वाली कंपनी ने भी ढाका–चटगांव रेलवे कॉरिडोर में एप्रोच रेलवे लिंक के साथ दूसरे भैरब रेलवे पुल के निर्माण के लिए एक ठेका करार पर भी हस्ताक्षर किये हैं.

इरकॉन ने हाल ही में तय समय से पहले श्रीलंका में 3 रेल परियोजनाओं अर्थात् कालूतारा–गाले–मतारा खंड (114 किलोमीटर), मेधवाचचिया–मधु रोड (43किलोमीटर) और ओमंथी–किल्ली नोची (63 किलोमीटर) पूरी की हैं और चालू कर दी हैं, जिससे कंपनी की ख्याति बढ़ी है.

भारत में सामरिक परियोजनाएं

हाल ही में, इरकॉन ने भारत में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा किया है जिसमें जम्मू एवं कश्मीर रेल लिंक परियोजना (बनिहाल–काजीगुंड–श्रीनगर–श्रीनगर–बारामुला), डीएमआरसी और कोलकाता की मेट्रो परियोजनाएं, ऊपरी सड़क पुल (बिहार, तमिलनाडु और पंजाब) पीजीसीआईएल के लिए सब स्टेशन परियोजना, बिजली वितरण परियोजना, एनएचएआई (धुले–पीपलगांव बीओटी परियोजना सहित) के लिए राजमार्गों का निर्माण और राज्य सरकारों के लिए सड़कों, अलीगढ़–गाजियाबाद तीसरी रेलवे लाइन तथा रेवाड़ी–अजमेर आमान परिवर्तन परियोजना शामिल हैं.

रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (क्रिस):

रेलवे सूचना प्रणाली केन्द्र (क्रिस) रेल मंत्रालय के अंतर्गत पंजीकृत एक स्वायत सोसाइटी है और इसकी स्थापना 1986 में की गई थी। यह रेलवे के इस क्षेत्र के विशेषज्ञों और अपने आईटी कर्मियों के उत्कृष्ट संयोजन का इस्तेमाल यात्री टिकटिंग और माल यातायात बीजक बनाने, मालगाड़ी और यात्रीगाड़ी परिचालन, क्रू का प्रबंधन और स्थायी एवं चल परिसंपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए रेलों के प्रमुख आईटी प्रणालियों का विकास और प्रबंधन में करती है।

वर्ष 2012-13 के दौरान क्रिस द्वारा शुरू की गई विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की कंप्यूटरीकरण की प्रगति निम्नानुसार रही है:

टिकटिंग और यात्री सूचना प्रणालियां:

यात्री आरक्षण प्रणाली (पीआरएस)

पीआरएस 9231 पीआरएस टर्मिनलों के साथ 2,685 स्थानों पर काम कर रहा है. अगस्त 2013 के दौरान ₹2,390.43 करोड़ का औसत यात्री आय के साथ औसतन 4.95 करोड़ यात्रियों को पीआरएस के माध्यम से बुक किया जा रहा है.

अनारक्षित टिकटिंग प्रणाली (यूटीएस):

अगस्त 2013 के दौरान 5,692 स्थानों पर 63.44 करोड़ यात्रियों को बुक किया गया और ₹1,334.40 करोड़ की कमाई हुई. सिकंदराबाद में यूटीएस डीआर प्रणाली परीक्षणाधीन है. 31/08/2013 तक मध्य, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व, पूर्व मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे में 1,029 एटीवीएम स्थापित किए गए हैं.

रिटायरिंग रूम:

अब 37 स्थानों पर रिटायरिंग रूम अनुप्रयोग का इस्तेमाल किया जा रहा है. अगस्त 2013 के दौरान कुल ₹64,13,061 की कमाई के साथ इस अनुप्रयोग के माध्यम से 24,349 रिटायरिंग रूम बुक किए गए थे.

पोर्टल वेबसाइटें:

भारतीय रेलवे की 38 वेबसाइटें हैं. सभी 38 वेबसाइटों को मानकीकृत सहित एक जैसी लगने और कार्य करने जैसी बनाया गया है.

गाड़ी संचालन:

कम्प्यूटरीकृत नियंत्रण चार्टिंग:

भारतीय रेलवे के सभी 77 मंडलों /क्षेत्र नियंत्रण कार्यालयों में सीओए अनुप्रयोग चल रहा है सभी 68 मंडल नियंत्रण कार्यालयों में सीओए और एफओआईएस, समीपवर्ती सीओए, राष्ट्रीय रेलगाड़ी पूछताछ प्रणाली (एनटीईएस) और एकीकृत कोचिंग प्रबंधन प्रणाली (आईसीएमएस) के बीच का एकीकरण पूरा हो गया है. नई समय तालिका कार्यक्रम

(आईसीएमएस) एप्लीकेशन में बनाए गए थे, और खंड नियंत्रकों के पास अद्यतन समय सारिणी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डेटा को सीओए एप्लीकेशन में सफलतापूर्वक अंतरित कर दिया गया था.

एफओआईएस चरण-II (टीएमएस विस्तार) :

नोडल अवधारणा के तहत गैर-डिवाइस स्थानों को सक्षम करने के लिए 99.9% से अधिक आरआर टीएमएस के माध्यम से बुक किए जाते हैं.

एकीकृत कोचिंग प्रबंधन प्रणाली (आईसीएमएस)

एफओआईएस नेट पर उपलब्ध आईसीएमएस अनुप्रयोग क्रिस, चाणक्यपुरी स्थित केंद्रीय सर्वर पर है. यह एक ब्राउजर आधारित एप्लीकेशन है और एफओआईएस नेट पर इसे किसी भी ग्राहक द्वारा चलाया जा सकता है. थिंक क्लाइंट/पीसी पर लगभग 1000 ग्राहक एफओआईएसनेट चला रहे हैं. इसमें समय-पालन विश्लेषण तथा निगरानी (पीएएम), कोचिंग परिचालन सूचना प्रणाली (सीओआईएस), कोच रखरखाव प्रबंधन (सीएमएम) जैसी तीन एप्लीकेशन हैं. भारतीय रेलवे पर दो मॉड्यूल एप्लीकेशन पहले से ही कार्यरत हैं, निर्माण के यांत्रिक भाग के लिए तीसरा मॉड्यूल को तीन पायलट स्थानों यथा नई दिल्ली कोचिंग डिपो, मुंबई सेंट्रल और लखनऊ डिपो में कार्यान्वित किया जा रहा है. नई दिल्ली और लखनऊ में कार्यान्वयन का कार्य प्रगति पर है. क्रिस टीम द्वारा उपयोगकर्ताओं के लिए हैंड होल्डिंग समर्थन दिया जा रहा है.

परिसंपत्ति प्रबंधन :

रेलपथ प्रबंधन प्रणाली

रेल पथ प्रबंधन प्रणाली की शुरूआत के लिए पायलट परियोजना 2010 में 6 पायलट मंडलों अर्थात आगरा, बिलासपुर, वाल्टेयर, सिकंदराबाद, सेलम और बेंगलूरू में पहले से ही कार्यान्वित कर दी गई है।

उसके बाद के वर्षों में टीएमएस को भारतीय रेल के 15 अन्य मंडलों अर्थात आद्रा, रायपुर, नागपुर, भुसावल, आसनसोल, मुगलसराय, रतलाम, मुरादाबाद, हैदराबाद, गुंटकल, विजयवाड़ा, गुंटुर, नांदेड़, अलीपुरद्वार और रांची पर कार्यान्वित किया गया था।

लोको शेड प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस)

निम्न कार्यात्मिकताओं के साथ एलएमएस सेंट्रल एप्लिकेशन का चरण II दिल्ली, लखनऊ और फिरोजपुर मंडलों में शुरू हो गया है।

i) इंजन के शेड में आने की भविष्यवाणी करना।

ii) इंजनों में खामियों के कारण गाड़ी समयपालन हानि मामलों को रिकार्ड करना

iii) मिस-लिंक लोको एंट्री।

iv) बकाया अनुसूची प्रबंधन

v) आउट शेड मेंटेनेंस वर्क एंट्री

भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसी):

भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड (आईआरएफसी)की स्थापना दिसम्बर, 1986 में एक सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी के रूप में भारतीय रेलवे की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए योजना परिव्यय को आंशिक रूप से वित्त पोषण हेतु बाजार से धन उगाही करने के उद्देश्य से की गई थी। बॉण्ड जारी करके, बैंकों/वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण और बाहरी व्यावसायिक ऋण/निर्यात क्रेडिट के द्वारा धन की उगाही की जाती है। सार्वजनिक उद्यम विभाग ने भारेविनि को विगत 15 वर्षों में 14 अवसरों पर 'उत्कृष्ट' का दर्जा दिया है। कंपनी ने तीन घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से ऋणदाता के धन की उच्चतम सुरक्षा को दर्शाने वाली उच्चतम क्रेडिट रेटिंग और चार प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेन्सियों से भारतीय 'प्रभुतासंपन्न' की रेटिंग के समतुल्य निवेश ग्रेड रेटिंग को बनाए रखा है।

कम्पनी ने 31 मार्च, 2013 तक रेल मंत्रालय को ₹97,481.67 करोड़ मूल्य की चल स्टॉक परिसंपत्तियां लीज़ पर दी हैं। रेल मंत्रालय 60 प्रतिशत चल स्टॉक परिसंपत्तियों जिसमें 6,654 रेल इंजन, 38,571 सवारी डिब्बे और 1,77,039 माल डिब्बे शामिल हैं, के लिए भारेविनि को लीज़ किरायों का नियमित रूप से भुगतान कर रहा है। पट्टा किराया रेलवे के सकल यातायात प्राप्तियों का लगभग 7.40% है। कंपनी ने 2012-13 के अंत तक ₹2,606 करोड़ की राशि भी सहयोगी रेलवे कंपनियों को मुहैया कराई है।

भारेविनि का लगातार लाभ कमाने का रिकार्ड है। इसने अभी तक अपने शेयरधारकों, सरकार को ₹1,778 करोड़ के लाभांश का भुगतान किया है। कम्पनी ने 2012-13 के दौरान ₹521.57 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया है। कंपनी का टर्न ओवर से ओवरहेड अनुपात 0.12% है।

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकोर):

मार्च, 1988 में भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकोर) की स्थापना देश के घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय कंटेनरीकृत परिवहन और व्यापार के अनुकूल मल्टी-मॉडल परिवहन और

संभार-तंत्र अवसंरचना का विकास करने के प्रमुख उद्देश्य से की गई थी। हालांकि इसकी 90 प्रतिशत से अधिक इनलैंड परिवहन सेवा रेल द्वारा की जाती है, बाजार मांग और परिचालनिक आवश्यकता /व्यावहारिकता के अनुसार सड़क/तटीय नौपरिवहन सेवाएं भी मुहैया कराई जाती हैं।

कॉनकोर के महत्वपूर्ण कार्य को तीन विशिष्ट गतिविधियों- कैरियर, टर्मिनल परिचालक और गोदाम/सीएफएस परिचालक के रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। कॉनकोर की मुख्य सामर्थ्य विभिन्न स्थलों पर टर्मिनलों का समर्पित नेटवर्क है। वर्ष 2012-13 के दौरान, कॉनकोर ने 2.5 मिलियन ट्वेंटी फीट इक्विलेंट यूनिटों (टीईयू) की सम्हलाई की।

कॉनकोर ने अपनी प्रदत्त पूंजी पर 2012-13 के लिए ₹227.46 करोड़ के लाभांश का भुगतान किया है।

वित्तीय विशेषताएं:

पिछले दो वर्षों में कॉनकोर का तुलनात्मक वित्तीय निष्पादन इस प्रकार है:

	2011-12	**2012-13**
टर्नओवर (₹ करोड़ में)	4,060.95	**4,406.16**
टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में शुद्ध लाभ	21.62	**21.33**
प्रतिशेयर आमदनी (₹ में)	67.54	**72.32**

कोंकण रेल निगम लिमिटेड (केआरसीएल):

केआरसीएल को 1990 में रेल मंत्रालय (51%), महाराष्ट्र (22%), कर्नाटक (15%), केरल (6%) और गोवा (6%) की इक्विटी साझेदारी में भारत के पश्चिमी घाट के साथ

अर्थात् रोहा से मंगलोर तक 741 किमी लंबी रेल लाइन के निर्माण के लिए स्थापित किया गया था। निर्माण चरण के दौरान निगम ने सुरंगों, पुलों और रेल लाइनों के निर्माण कार्य में वृहतर अनुभव प्राप्त किया था और इस टैलेंट पुल को बड़ी निर्माण परियोजनाओं में भी उपयोग करना शुरू कर दिया है।

परिचालन निष्पादन:

गाड़ी परिचालन:

वर्ष 2012-13 के दौरान, कोंकण रेलवे पर रोल ऑन-रोल ऑफ सेवाओं को शामिल करते हुए 5 जोड़ी पैसेंजर गाड़ियों और 18 माल गाड़ियों सहित प्रतिदिन औसतन 33 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस चलती हैं। अभिनव रोल ऑन-रोल आफ सेवाओं ने सफलतापूर्वक 14 वर्ष पूरे कर लिए हैं और निगम ने यातायात के प्रवाह से ₹50.07 करोड़ का उच्चतम राजस्व अर्जित किया है। प्रारंभिक लदान, जो रेल प्रणाली को लाभदायक बनाने के लिए एक सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानदंड समझा जाता है, 2011-12 के 2.4 मिलियन टन की तुलना में वर्ष के दौरान 3.28 मिलियन टन रहा। लाइन क्षमता को बेहतर बनाने के लिए कोलाड, सिंधुदुर्ग और बल्ली में तीन लूप लाइनों को भी जोड़ा गया था।

ख) परियोजनाएं:

i) उधमपुर-श्रीनगर-बारमूला रेल लिंक (यूएसबीआरएल) परियोजना:

वर्ष 2012-13 के दौरान, सुरंगों के 4.13 किमी कार्य पूरे किए गए थे जो एक वर्ष में सबसे अधिक प्रगति है। 28 किमी लंबी 14 सुरंगों के कार्य प्रगति पर हैं। अभी तक, कुल 7 सुरंगें बना ली गई हैं, जिनमें से 4 सुरंगों को वर्ष 2012-13 में पूरा किया गया था। संचयी आधार पर, 18.82 किमी. लंबाई का सुरंग कार्य पूरा हो गया है। चेनाब नदी पर विशेष पुल के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2012-13 के दौरान, यूएसबीआरएल में ₹329 करोड़ का सर्वश्रेष्ठ टर्नओवर प्राप्त हुआ था। ₹3,382 करोड़ के कुल अनुमान की तुलना में ₹1756 करोड़ का संचयी टर्नओवर

प्राप्त किया गया था।

ii) केआरसीएल ने जून, 2007 में अपनी शुरूआत से पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर टक्कररोधी उपकरण प्रणाली को परिचालित किया है। इलैक्ट्रॉनिक टेस्ट और डेवलपमेंट सेंटर (ईटीडीसी), चेन्नै द्वारा बेहतर एसीडी सॉफ्टवेयर वर्जन 1.1.2 को सफलतापूर्वक वेलीडेट किया है। बेहतर एसीडी सॉफ्टवेयर को तिनसुकिया मंडल में भी जांचा गया है और संपूर्ण पूर्वोत्तर सीमा रेलवे पर लागू किए जाने के लिए आरडीएसओ से स्वीकृति मिलने की प्रतीक्षा है।

भू-संरक्षा कार्य:

निगम ने कटिंग को स्थिर करने और मानसून में भी बेहतर गति के लिए ट्रैक को सुरक्षित बनाने के लिए वर्ष 2012-13 के दौरान भू-संरक्षा कार्यों पर ₹26.02 करोड़ खर्च किए हैं।

वित्तीय निष्पादन:

निगम का कुल राजस्व पिछले वर्ष के कुल राजस्व ₹1,001 करोड़ (एक हजार एक करोड़ रुपए) की तुलना में बढ़कर ₹1,136 करोड़ (एक हजार एक सौ छत्तीस करोड़ रुपए) हो गया है। कंपनी ने वर्ष के दौरान ₹128 करोड़ का परिचालन अधिशेष अर्जित किया। वर्ष 2011-12 के 82.12 प्रतिशत की तुलना में चालू वर्ष में परिचालन अनुपात कर्मचारियों, ईंधन और किराया प्रभारों में वृद्धि के कारण 95 प्रतिशत रहा। वर्ष 2012-13 के अंत में निगम का शुद्ध मूल्य ₹1,340 करोड़ (एक हजार तीन सौ चालीस करोड़ रु.) रहा।

भारतीय रेलटेल निगम लिमिटेड (रेलटेल):

देश के सभी भागों में राष्ट्रव्यापी ब्राडबैंड टेलीकॉम और मल्टीमीडिया नेटवर्क तैयार करने, आधुनिक संचार अवसंरचना उपलब्ध कराकर गाड़ियों के परिचालन और संरक्षा

प्रणालियों और नेटवर्क के तेजी से आधुनिकीकरण में रेलवे को सहायता करने और इसके टेलीकॉम नेटवर्क के वाणिज्यिक दोहन द्वारा राजस्व अर्जित करने के उद्देश्य से सितंबर, 2000 में रेलटेल का गठन किया गया था।

रेलटेल के पास डीओटी का अवसंरचना प्रदाता कोटि I आईएसपी लाइसेंस है। इसके अतिरिक्त इसके पास राष्ट्रीय लंबी दूरी (एनएलडी) सेवा लाइसेंस है। इसके अलावा, रेलटेल द्वारा डीओटी से आईपी के रूप में रजिस्ट्रेशन भी प्राप्त किया गया है। रेलटेल ने देश भर में 42,000 मार्ग किमी ओएफसी से अधिक पर आधुनिक एसटीएम-16/64/डीडब्यूडीएम नेटवर्क लगाया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय निष्पादन इस प्रकार है:

कंपनी ने पिछले तीन वर्षों के दौरान ₹100 करोड़ से अधिक का कर पूर्व लाभ कमाया है।

वर्तमान में रेलटेल एक ऋणमुक्त कंपनी है।

कंपनी ने अपनी आय से रेलवे को राजस्व में भागीदारी और डीओटी को लाइसेंस फीस का भुगतान किया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार के राजस्व में हिस्सेदारी और लाइसेंस फीस निम्नानुसार है:

			(₹ करोड़ में)
	2010-11	2011-12	**2012-13**
राजस्व में रेलवे की हिस्सेदारी	21.07	16.09	**18.14**
डीओटी को लाइसेंस फीस	11.00	12.70	**27.51**

कंपनी लागू सीमा तक कॉरपोरेट गर्वनेंस पद्धतियों का अनुसरण कर रही है। इसके अतिरिक्त, यह अपने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व का निर्वाहन करती है और इसने देश के दक्षिणी भाग में विभिन्न पंचायतों को ब्रॉडबैंड संपर्कता उपलब्ध कराने में ₹2.68 करोड़ का व्यय वहन किया था।

वित्तीय:

			(₹ करोड़ में)
विवरण	2010-11	2011-12	**2012-13**
अंश पूंजी	320	320	**320**
कुल आय	363	404	**435**
कर पूर्व शुद्ध लाभ	107	116	**142**
कर पश्चात शुद्ध लाभ	95	85	**111**
सकल मार्जिन	170	232	**232**
शुद्ध मूल्य	633	707	**796**
रिजर्व एवं अधिशेष	317	381	**475**
रेल मंत्रालय को लाभांश भुगतान	13	14	**15**
कर्मचारियों की संख्या	360	359	**459**
प्रतिनियुक्तियों की संख्या	87	95	**98**
एमओयू रेटिंग	अच्छा	अच्छा	**उत्कृष्ट (संभावित)**

रेलटेल को सरकारी परियोजनाओं के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त, भारतीय रेल में आधुनिक सिगनल प्रणाली प्रौद्योगिकी के क्रियान्वयन के लिए नेटवर्क सृजन में भी अवसरों को तलाशा जा रहा है। इसके अतिरिक्त, परामर्श, डाटा सेंटर टेलीप्रेजेंस, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के क्षेत्रों में नई सेवाओं की शुरूआत से राजस्व अर्जन के लिए नए अवसर भी खुलेंगें।

भारतीय रेलटेल निगम लिमिटेड, गुड़गांव

भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम लिमिटेड (आईआरसीटीसी):

रेल खानपान, पर्यटन और यात्री सुविधाओं के क्षेत्रों में भारतीय रेल की विपणन और सेवा क्षमताओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 27.09.1999 को निगमित किया गया था। कंपनी ने 2 दिसंबर, 1999 को व्यापार शुरू करने का प्रमाणपत्र प्राप्त किया। कंपनी की प्राधिकृत अंश पूंजी ₹50 करोड़ है और प्रदत्त अंश पूंजी ₹20 करोड़ है, इसे पूर्ण रूप से रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अभिदत्त किया गया है। कार्यकारी बोर्ड की स्थापना के पश्चात 1 अगस्त, 2001 को निगम ने पूर्ण रुप से कार्य करना प्रारंभ किया। आईआरसीटीसी, भारत सरकार की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी वाला रेल मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत पर्यटन सेवा क्षेत्र में एक शेड्यूल ''बी''/सीपीएसई है। इसका पंजीकृत और निगम कार्यालय नई दिल्ली में है।

वित्तीय प्रदर्शन की झलकियां:

वर्ष 2012-13 के दौरान, 2011-12 के ₹554.11 करोड़ के मुकाबले ₹719.69 करोड़ की कुल आय को प्राप्त किया जिससे 29.88 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। मुख्यत: पर्यटन खंड आमदनी में बहुत अधिक वृद्धि के कारण आय 2011-12 में ₹98.95 करोड़ के मुकाबले 2012-13 में ₹188.71 करोड़ हो गई। निगम का शुद्ध मूल्य 31.03.2012 के ₹246.70 करोड़ के मुकाबले 31.3.2013 में ₹291.77 करोड़ हो गया।

निगम द्वारा निम्न तरीके से लाभ अर्जित किया गया:

		(₹ करोड़ में)
विवरण/समाप्त होने वाला वर्ष	31 मार्च, 2012	**31 मार्च, 2013**
कर पूर्व लाभ	76.54	**92.41**
कर के लिए प्रावधान	28.00	**33.57**
आस्थारगित कर	-	**-**
कर पश्चात लाभ	48.54	**58.84**
अग्रेषित लाभ	14.50	**16.78**
रिजर्व को अंतरित	35.00	**35.00**
लाभांश (लाभांश कर सहित)	11.25	**13.77**
तुलन पत्र को अग्रेषित लाभ	16.78	**26.68**

निगम ने पिछले वर्ष के ₹25.64 करोड़ की तुलना में 2012-13 में भारतीय रेल की आमदनी में ₹28.19 करोड़ का योगदान दिया। टिकटिंग पोर्टल www.irctc.co.in. द्वारा पिछले वर्ष के दौरान ₹9,646 करोड़ की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान ₹12,419 करोड़ मूल्य की टिकटें बुक की गई।

आईआरसीटीसी द्वारा बुक की गई टिकटों की संख्या पिछले वर्ष बुक की गई 11.61 करोड़ टिकटों के मुकाबले 2012-13 में 14.06 करोड़ तक बढ़ी। तदनुसार, इंटरनेट टिकटिंग से कुल आमदनी 2011-12 में ₹160.64 करोड़ की तुलना में 2012-13 में ₹187.94 करोड़ हो गई। पिछले वर्ष की तुलना में टिकटों की बिक्री में 21% वृद्धि हुई।

आईआरसीटीसी से मोबाइल बुकिंग एक कदम और आगे बढ़ी जब माननीय रेल मंत्री जी ने 28 जून, 2013 को एसएमएस द्वारा टिकटों की बुकिंग शुरू की। इस सेवा में किसी इंटरनेट सुविधा की आवश्यकता नहीं है। अब कोई भी व्यक्ति मोबाइल का प्रयोग कर इस उपयोगकर्ता हितैषी सेवा द्वारा मोबाइल फोन से अपनी टिकट बुक कर सकता है।

पिछले पांच वर्षों की वित्तीय झलकियां निम्नानुसार हैं:

विवरण	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	**2012-13**
कुल आय	618.77	721.97	764.93	554.11	**719.69**
कुल व्यय	536.68	614.63	620.69	462.83	**611.24**
सकल मार्जिन	82.09	107.34	144.24	91.28	**108.45**
कर पूर्व लाभ	73.85	94.76	129.79	76.54	**92.41**
कर प्रावधान	27.35	31.71	69.00	28.00	**33.57**
शुद्ध लाभ	46.50	63.05	60.79	48.54	**58.84**
अनुपात					
सकल मार्जिन/कुल आय	13.27%	14.87%	18.86%	16.47%	**15.06%**

2011–12 में ₹197.64 करोड़ की तुलना में 2012–13 में विभागीय खानपान से कुल आमदनी ₹241.15 करोड़ थी। गैर-रेलवे खानपान (एनआरसी) ने 2011–12 के ₹10.79 करोड़ की तुलना में 2012–13 में विभागीय खानपान संव्यवहार ने कुल आमदनी में ₹28.64 करोड़ का योगदान दिया। एनआरसी आमदनी में वृद्धि मुख्यतः नई एनआरसी इकाइयों के खुलने, फूड फैक्ट्री, नोएडा के परिचालन आदि के कारण हुई। लाइसेंसशुदा खानपान इकाइयों से वर्ष 2011–12 में ₹30.38 करोड़ की तुलना में वर्ष 2012–13 में ₹21.44 करोड़ की आय सृजित हुई। ₹8.94 करोड़ की कमी मुख्यतः लाइसेंसशुदा खानपान खंड रेलों को सौंपने के कारण हुई।

वर्ष के दौरान, 12 अदद फूड प्लाजा/फास्ट फूड इकाइयों को खोला गया जिससे परिचालनिक इकाइयों की कुल संख्या बढ़कर 107 हो गई। सेंट्रल किचन की क्षमता प्रति दिन 10,000 भोजन की है। इकाई एनसीआर क्षेत्र में नोएडा/ग्रेटर नोएडा/गुड़गांव में कॉरपोरेट क्षेत्र में भोजन की आपूर्ति कर रही है। सेंट्रल किचन, नोएडा नई दिल्ली/हजरत निजामुद्दीन से जाने वाली सभी राजधानी एवं दूरांतो विभागीय गाड़ियों को 6000 स्नैक्स प्रति दिन और अहमदाबाद राजधानी और सियालदह दूरांतो को 2,000 भोजन प्रति दिन की भी आपूर्ति कर रहा है।

वर्ष 2012–13 के दौरान, निगम ने एक पायलट परियोजना के रूप में एयरपोर्ट लाउंजों की तरह रेलवे यात्रियों को प्रस्थान-पूर्व एवं आगमन-पश्चात सुविधाओं को देने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ''एक्जीक्यूटिव लाउंज'' की स्थापना की है। यह एक नया संव्यवहार क्षेत्र है और इस प्रकार के लाउंजों को 50 स्टेशनों पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

पिपावाव रेलवे कारपोरेशन लि. (पीआरसीएल):

सुरेन्द्रनगर-राजुला-पिपावाव पत्तन (एपीएम टर्मिनल, पिपावाव) आमान परिवर्तन

करने और नई लाइन परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए रेल मंत्रालय और गुजरात पिपावाव पत्तन लि. (जीआरपीएल) की समान इक्विटी वाली हिस्सेदारी से पिपावाव रेल निगम लि. (पीआरसीएल) नामक एक संयुक्त उद्यम की स्थापना की गई थी। यह निजी क्षेत्र की भागीदारी से निष्पादित की जाने वाली प्रथम रेल अवसंरचना परियोजना है। पिपावाव रेल निगम लिमिटेड को 33 वर्षों के लिए इस परियोजना खंड का निर्माण करने, परिचालन करने और देखरेख करने का रियायती अधिकार प्राप्त है। पिपावाव रेल निगम लिमिटेड को रेल अधिनियम, 1989 में निहित रेल प्रशासन के दायित्व, कर्तव्य और अधिकार प्राप्त हैं और उसे कार्गो के परिवहन पर अधिक छूट प्रदान करने का अधिकार है। पिपावाव रेलवे कारपोरेशन लि. ने रेल मंत्रालय के निकट समन्वय से भारत में डबल स्टैक कंटेनरों की शुरूआत की अगुआई की तथा पिपावाव मार्ग पर 23.3.2006 को जयपुर से पिपावाव तक पहली डबल स्टैक कंटेनर गाड़ी चली।

पिपावाव रेल निगम लिमिटेड को पिपावाव, मुंद्रा, चेन्नै, एन्नौर, विजाग और कोच्चि एवं उनके आंतरिक भागों के पत्तनों को सेवित करने वाले रेल मार्गों पर कंटेनर गाड़ियां चलाने की अनुमति है। कंपनी ने 20 अगस्त, 2009 को कंटेनर परिचालन शुरु कर दिया था।

वर्ष 2012-13 के दौरान, पिपावाव रेल निगम लिमिटेड ने 5,059 कंटेनर गाड़ियों सहित 6,302 गाड़ियों की सम्हलाई की और 6.86 मिलियन टन माल की ढुलाई की। वर्ष 2012-13 के दौरान, माल परिचालन से कुल विभाजित आय ₹178.98 करोड़ थी जिससे पूर्व वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा लगभग ₹67.36 करोड़ (लगभग-बिना लेखा परीक्षा के) के कर से पहले शुद्ध लाभ हुआ जो पूर्व वर्ष के ₹43.67 करोड़ के लाभ से 54% अधिक था। इससे कंपनी का शुद्ध मूल्य भी लगभग ₹150.79 करोड़ से लगभग ₹225 करोड़ (अनुमानित) तक बढ़ गया।

पिपावाव रेलवे के विभिन्न खंडों पर 15 जोड़ी पैसेंजर गाड़ियां भी चल रही हैं। 2011-12 तथा 2012-13 के तुलनात्मक आंकड़े इस प्रकार हैं:-

	2011-12	**2012-13**
चलाई गई गाड़ियों की कुल संख्या	5479	**6,302**
कंटेनर गाड़ियों की संख्या	3927	**5,059**
थोक में चलाई गई गाड़ियों की संख्या	821	**708**
खाली गाड़ियों की संख्या	731	**535**
कार्गो(मिलियन टन में)	6.83	**6.86**
विभाजित राजस्व(करोड़ रु.में)	151.28	**178.98**
यात्री गाड़ियों की संख्या	जोड़ी	**15 जोड़ी ***

* इसमें वे दो गाड़ियां, जो दैनिक रुप से चलती हैं, भी शामिल हैं जिन्हें एक गाड़ी में बदल दिया गया है।

बाजार विस्तार में नई पहलकदमियां:

पीआरसीएल ने रेल मंत्रालय के साथ निकट समन्वय बनाकर भारत में डबल स्टैक कंटेनर गाड़ियों की शुरुआत करने में अग्रणी भूमिका अदा की तथा 23 मार्च 2006 को पिपावाव मार्ग पर जयपुर से पिपावाव तक पहली डीएससी गाड़ी चलाई।

17 जुलाई 2013 को एपीएम टर्मिनल से सीएमएल के (कथुवास-ग्रीनफील्ड पीएफटी से कॉनकोर नीमराणा तक) पिपावाव पर पहली 9½ x 9½ फीट (हाई क्यूब) डबल स्टैक कंटेनर गाड़ी चलाई गई।

लिलियामोटा स्टेशन में बोरीबंद आवक परेषणों को सम्हालने के लिए रेल लेवल प्लेटफार्म की व्यवस्था हो जाने से इसे 28 सितम्बर, 2012 को माल यातायात के लिए खोल दिया गया है।

सीमेंट की सम्हलाई करने के लिए पिपावाव स्टेशन(पीपीवीएस) पर पक्की सतह बनाने का कार्य जनवरी 2013 को पूरा कर दिया गया है।

खंड पर रेलपथ क्षमता संवर्धन के पहले चरण में कुंडली तथा लथीडाड प्रत्येक स्टेशन में एक लूप के निर्माण का कार्य लगभग ₹8.70 करोड़ की अनुमानित लागत पर (वित्त वर्ष 2013-14) शुरु किया गया है ताकि पीआरसीएल सेक्शन पर बढ़े हुए यातायात को सम्हाला जा सके।

रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल):

रेल क्षमता परियोजनाओं के लिए गैर-बजटीय संसाधन जुटाने और उन्हें फास्ट ट्रैक आधार पर कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 2003 में रेल मंत्रालय के अधीन एक विशेष प्रयोजन योजना (एसपीवी) के रूप में रेल विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी।

2012-13 के दौरान आरवीएनएल ने 568 कि.मी. की परियोजना की लंबाई का कार्य पूरा किया जिसमें 267 कि.मी. का दोहरीकरण शामिल है, जो भारतीय रेलवे द्वारा प्राप्त किए गए कुल 700 कि.मी. का लगभग 40% है तथा इसमें 303 कि.मी. बिजली संबंधी विशुद्ध कार्य है। इसके अलावा, दोहरीकरण तथा अन्य परियोजनाओं के रूप में 238 कि.मी. विद्युतीकरण का कार्य भी पूरा किया। यह भारतीय रेलवे द्वारा वर्ष में निष्पादित किए गए बिजली संबंधी कार्यों का कुल अनुमानतः 40% है। संचयी रूप से 31.3.13 तक आरवीएनएल ने 36 परियोजनाएं पूरी की हैं, जिसमें नई लाइनों का 194 कि.मी. का कार्य शामिल है।

2012-13 के दौरान, कंपनी परियोजना नियोजन की बुनियाद का निर्माण करने तथा पिछले वर्षों में आरवीएनएल को निष्पादित करने के लिए सौंपे गए परियोजना के ठेकों को प्रदान करने तथा जुलाई 2012 में एडीबी ऋण की दूसरी खेप को स्वीकृत करने में समर्थ हो सकी। परियोजना निष्पाादन के शुरू हो जाने के परिणामस्वरूप कंपनी ने पहली बार ₹2,000 करोड़ के टर्न ओवर के आंकड़े को पार करके 2012-13 में ₹2,116.85 करोड़ का आंकड़ा प्राप्त किया जो पिछले वर्ष 2011-12 के ₹1597.92 करोड़ की तुलना में 32 प्रतिशत की वृद्धि का द्योतक है। कंपनी का सकल लाभ 2011-12 के ₹119.3 करोड़ से बढ़कर 2012-13 में ₹167.5 करोड़ हो गया तथा कर पश्चात लाभ ₹98.4 करोड़ से बढकर ₹135.6 करोड़ हो गया। कंपनी का शुद्ध मूल्य 2011-12 के अंत में ₹2,312 करोड़ से बढ़कर 2012-13 के अंत में ₹2,418 करोड़ हो गया।

2012-13 में उपरोक्त बेहतर वित्तीय निष्पादन को देखते हुए आरवीएनएल ने पिछले वर्ष के ₹20 करोड़ के लाभांश का भुगतान करने की तुलना में 2012-13 में ₹27 करोड़ रु. के लाभांश का भुगतान किया। रेल मंत्रालय को आरवीएनएल द्वारा भुगतान किया गया संचयी लाभांश ₹82.5 करोड़ है।

परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए आईआरएफसी से ₹2,183 करोड़ के उधार के अतिरिक्त ₹4,324 करोड़ की कुल प्रत्याशित लागत के साथ 5 परियोजना के विशिष्ट विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) की स्थापना के लिए संसाधन जुटाने में भी रेल विकास निगम लिमिटेड ने भूमिका अदा की जिसके लिए रेल विकास निगम लिमिटेड का इक्विटी अंशदान ₹546 करोड़ अर्थात् 12.6 प्रतिशत है। ₹3,778 करोड़ की बकाया निधि दावेदारों के इक्विटी शेयर तथा नान रिकोर्स ऋण के माध्यम से मुहैया की जाएगी। रेल विकास निगम लिमिटेड के विशेष प्रयोजन वाहनों में कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड कृष्णापत्तनम रेलवे कंपनी लिमिटेड, भरूच दाहेज रेलवे कंपनी लिमिटेड, हरिदासपुर पारादीप कंपनी लिमिटेड तथा अंगुल, सुकिन्दा रेलवे लिमिटेड शामिल हैं।

अपने नियमित कार्यों के अतिरिक्त, रेल विकास निगम लिमिटेड उन स्थानों जहां उसकी परियोजनाएं स्थित हैं, वहां पिछड़े समुदायों के उत्थान के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व वाली परियोजनाओं को कार्यान्वित करके, जिसमें स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, के संबंध में वर्ष के दौरान ₹3.01 करोड़ खर्च करके अपने दायित्व का निर्वाह कर रहा है। आरवीएनएल निरन्तर रूप से विकास करने के प्रति वचनबद्ध है, इसी भूमिका के रूप में आरवीएनएल ने 2012-13 में 6000 वृक्ष लगाए हैं।

रेल भूमि विकास प्राधिकरण (आरएलडीए):

रेल भूमि विकास प्राधिकरण रेल मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक प्राधिकरण है,

जिसका गठन गैर-टैरिफ राजस्व उपार्जन के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा सौंपे गए रेलवे भूमि का विकास करने के लिए भारतीय रेल अधिनियम, 1989 में संशोधन करके किया गया था। आरएलडीए की स्थापना दिनांक 31.10.2006 को असाधारण राजपत्रित अधिसूचना की शर्तों के अनुसार किया गया था। आरएलडीए के कार्य-कलाप असाधारण राजपत्र में भी 04.01.2007 को अधिसूचित कर दिए गए हैं।

प्राधिकरण के कार्य कलाप :

खाली पड़ी रेल भूमि का वाणिज्यक विकासः

खाली पड़ी रेल भूमि का वाणिज्यिक विकास करने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा आरएलडीए को सौंप दिए गए हैं। आरएलडीए द्वारा वित्त वर्ष के दौरान कुल ₹338.40 करोड़ की कुल आमदनी प्राप्त हुई है। 31.03.2012 से पहले वाणिज्यिक विकास के लिए पांच स्थानों यथा ग्वालियर, बेंगलूरू, गया, दिल्ली, सराय रोहिल्ला तथा विजयवाड़ा सौंपे गए थे। इसके अलावा, तीन स्थानों यथा ग्वालियर, बेंगलूरू तथा गया के लिए करार पहले ही निष्पादित कर दिए गए हैं। दिल्ली, सराय रोहिल्ला के संबंध में समझौता विकासकर्ता* के अनुरोध पर लंबित है। विजयवाडा के संबंध में, केबिनेट की स्वीकृति के अभाव में करार पर हस्ताक्षर में विलम्ब होने से एलओए निरस्त कर दी गयी है।

2012-13 के दौरान आरएलडीए ने वाणिज्यिक विकास के लिए आरएलडीए को 7 नए स्थान सौंपे हैं तथा सौंपे गए 9 स्थानों को वापस लेने के लिए उनकी सहमति भेजी है। इस प्रकार, आरएलडीए को कुल 136 स्थान सौंप दिए गए हैं जिसमें से 47 स्थानों को वापस लेने का प्रस्ताव किया गया है।

बहुकार्यात्मक परिसरों (एमएफसी) का निर्माणः

इरकॉन, राइटस, आरवीएनएल तथा प्राइवेट सैक्टर विकासकर्त्ताओं के माध्यम से

*31.05.2013 को विकास समझौता निष्पादित किया।

आरएलडीए को बहु कार्यात्मक परिसरों को विकसित करने की जिम्मेदारी सौंप दी गयी है। एमएफसी शॉपिंग, फूड स्टॉल/रेस्टोरेंट, बुक स्टॉल, पीसीओ बूथ, एटीएम, औषधियों तथा वेरायटी स्टोर, बजट होटल, पार्किंग स्थल तथा रेलवे स्टेशनों पर रेल उपयोग कर्त्ताओं के लिए इसी प्रकार की अन्य सुविधाओं जैसी बहु-सुविधाएं स्टेशन परिसर में उपलब्ध कराएंगे। अपफ्रन्ट लीज प्रीमियम के भुगतान पर अथवा पीएसयू के साथ राजस्व की भागीदारी पर समझौता ज्ञापन से तथा प्राइवेट सेक्टर डेवलपर्स के साथ खुली निविदा के माध्यम से 30 से 45 वर्ष के लिए स्थल पट्टे पर दिए जाएंगे। अभी तक 46 बहुकार्यात्मक परिसर या तो पीएसयू अर्थात इरकॉन (24), राइट्स (20) तथा आरवीएनएल (2) के जरिए विकसित किए जा रहे हैं तथा 120 बहुकार्यात्मक परिसर आरएलडीए द्वारा विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। 2012-13 के दौरान 3 बहुकार्यात्मक परिसर अर्थात झांसी, कटक तथा कटरा को विकसित करने के लिए करार निष्पादित कर दिया गया है।

स्टेशनों का पुनर्विकास :

भारतीय रेल का आधुनिकीकरण का विशेषज्ञ ग्रुप, जिसके अध्यक्ष सैम पित्रोदा हैं, ने 100 प्रमुख स्टेशनों को तुरंत आधुनिक बनाने तथा 10 वर्ष में कुल 770 स्टेशनों को आधुनिक बनाने की सिफारिश की है। रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलेपमेंट कोर्पोरेशन लि. (आईआरएसडीसी) नामक एक संयुक्त उद्यम, जिसमें इरकॉन तथा आरएलडीए की 51:49 के अनुपात से इक्विटी भागीदारी है, की स्थापना 12.04.2012 को की गई जिसके पास ₹100 करोड़ की प्राधिकृत शेयर पूंजी है।

भारतीय समर्पित माल यातायात गलियारा लिमिटेड (डीएफसीसीआईएल):

माल यातायात गलियारा (डीएफसी) परियोजना भारत सरकार द्वारा अभी तक शुरु की गई रेल अवसंरचना परियोजना में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण परियोजना है। माल

यातायात गलियारा भारतीय समर्पित माल यातायात गलियारा लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, इस उद्देश्य के लिए एक विशेष प्रयोजन वाहन सृजित किया गया है। भारतीय समर्पित माल यातायात गलियारा रेल मंत्रालय का एक पूर्ण रुप से सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व वाला उपक्रम है जिसका निगमीकरण 30 अक्टूबर, 2006 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत किया गया. कंपनी को समर्पित माल यातायात गलियारों की लाइनों की योजना बनाना, निर्माण करना, रख-रखाव करना तथा उनका परिचालन करने का अधिकार है. शुरुआत के रुप में समर्पित माल यातायात गलियारा पश्चिमी तथा पूर्वी ट्रंक मार्गों पर विकसित किया जा रहा है। पश्चिमी माल यातायात गलियारा (1,499 कि.मी.) मुंबई में जवाहरलाल नेहरु पोर्ट (जेएनपीटी) से दिल्ली के निकट दादरी तक होगा जो महाराष्ट्र तथा गुजरात तक उत्तर के भीतरी भागों में मौजूदा तथा उभरते हुए पत्तनों के बीच कंटेनर तथा आयातित कोयले की ढुलाई की आवश्यकताओं को अधिकांश रुप से पूरा करेगा. पूर्वी माल यातायात गलियारा पंजाब में लुधियाना से कोलकाता के निकट दानकुनी(1,839 कि.मी.) तक होगा जो अधिकांश रुप से कोयला तथा इस्पात यातायात को सेवित करेगा. दोनों गलियारे दादरी के निकट जुड़ेंगे।

गलियारे का वित्त पोषण रेल मंत्रालय की इक्विटी के जरिए तथा जापान इंटरनेशनल कार्पोरेशन एजेन्सी (जेआईसीए) तथा विश्व बैंक बहुपक्षीय वित्तपोषण(ऋण) से किया जा रहा है. पश्चिमी डीएफसी (मुगलसराय-इलाहाबाद-कानपुर-खुर्जा-दादरी और खुर्जा-लुधियाना) का वित्त पोषण विश्व बैंक द्वारा किया जा रहा है. पूर्वी डीएफसी का दानकुनी-सोननगर खण्ड पीपीपी के जरिए कार्यान्वित किया जाएगा. पूर्वी तथा पश्चिमी डीएफसी 9 राज्यों, 66 जिलों तथा 1,900 गांवों से होकर गुजरता है।

डीएफसी के कार्यान्वयन से माल यातायात संचलन पर दो प्रमुख प्रभाव पैदा होने की संभावना है, सड़क से माल यातायात के शिफ्ट होने के फलस्वरुप रेल में गुणांक रुप से वृद्धि होगी और बेहतर प्रोद्यौगिकी को अपनाने से रेल माल यातायात की ऊर्जा क्षमता बेहतर होने से कार्बन फुट प्रिंट्स में महत्वपूर्ण कमी आएगी. उच्चतर धुरा भार तथा

वाइडर मैक्सीमम मूविंग डाइमेनसन (एमएमडी) वाले डीएफसी परिवहन तंत्र में बदलाव लाएगा. निर्धारित सेवाओं में तेजी आने से संभारतंत्र लागत में महत्वपूर्ण कमी आने की संभावना है। नेटवर्क से चिर प्रतीक्षित संभारतंत्र का पूर्ण रुप से हल होने की संभावना है ताकि व्यापार में ऊर्जा कुशल रेल परिवहन का इस्तेमाल हो सके।

भारतीय रेलों की ओर से परियोजनाओं के लिए भारतीय माल यातायात गलियारा लिमिटेड भूमि अधिग्रहण की प्रमुख चुनौतियों को सफलतापूर्वक पूरा करने में समर्थ हुआ है। 31 मार्च 2013 तक 8,846 हेक्टेयर भूमि (डब्ल्यूडीएफसी: 5,680 हेक्टेयर में से 5,147 तथा ईडीएफसी: 4,807 हेक्टेयर में से 3,700 हेक्टेयर भूमि) प्रदान की गई है। 2012-13 में पूर्वी माल यातायात गलियारे पर कानपुर तथा खुर्जा के बीच 343 कि.मी. लम्बे दोहरे रेलपथ के निर्माण के लिए पूर्वी माल यातायात गलियारे पर ₹3,300 करोड़ के मूल्य का प्रथम प्रमुख सिविल वर्क ठेका प्रदान करके डीएफसी ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। मार्च 2013 तक पश्चिमी माल यातायात गलियारा के वेतरना तथा उतरन खंड के बीच कुल 21 पुलों का कार्य पूरा किया गया।

परियोजना पर 31 मार्च 2013 तक ₹2,430.02 करोड़ का संचयी व्यय किया गया है। वर्ष 2012-13 के दौरान परियोजना कार्यान्वयन पर सकल व्यय ₹1430.75 करोड़ है।

पश्चिमी माल यातायात गलियारे का दृश्य

मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमआरवीसी):

मुंबई शहरी परिवहन परियोजना नामक एक एकीकृत रेल-सह-रोड शहरी परियोजना के रेल कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए रेल मंत्रालय तथा महाराष्ट्र सरकार के बीच 51:49 के अनुपात में शेयर की गयी ₹25 करोड़ मूल्य की इक्विटी पूंजी के साथ 12.7.1999 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत निगमीकृत मुंबई रेल विकास कार्पोरेशन लिमिटेड (एमआरवीसी लिमि.) रेल मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।

एमआरवीसी का उद्देश्य/विजन:

दैनिक यात्रियों को पर्याप्त रूप से रेल सेवाएं मुहैया कराने के लिए मुंबई उपनगरीय खंड में एक कुशल, सुरक्षित तथा अक्षुण्ण आधुनिक अवसंरचना का विकास करना।

मुंबई शहरी परिवहन परियोजना - एमयूटीपी चरण - I :

एमयूटीपी (रेल घटक) को दो चरणों (चरण-I और चरण II) में विभाजित किया गया है, के रेल घटक की लागत ₹4,501.80 करोड़ है जिसमें से ₹1,600 करोड़ का ऋण विश्व बैंक से लिया गया था. शेष खर्च को महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय के बीच समान रूप से बांटा गया है. सभी कार्य पूरे हो चुके हैं और मार्च 2012 को एमयूटीपी-I बंद कर दिया गया है.

एमयूटीपी-I के पूरा होने के बाद उपार्जित प्रमुख लाभ

ईएमयू रेकों की खरीद:

- सभी 101 रेक (909 डिब्बे) प्राप्त हुए
- अतिरिक्त मुहैया सेवाएं-458
- 9 कार रेकों से 12-कार रेकों तक संवर्धित सेवाएं-1048
- सृजित अतिरिक्त वहन क्षमता-33 %
- वाहन किलोमीटर में वृद्धि-35%
- भीड़भाड़ में कमी-20%
- पश्चिम रेलवे पर 15 कार सेवाओं की शुरुआत

अतिरिक्त गलियारे बिछाना:

- पश्चिम रेलवे के बोरीवली-विरार और मध्य रेलवे के कुर्ला-ठाणे के बीच अतिरिक्त गलियारे.

- गाड़ियों की बढ़ती संख्या के लिए अतिरिक्त मार्ग की व्यवस्था करना.
- उपनगरीय परिचालन से मुख्य लाइन परिचालन को अलग करना.
- विरार से दहानू रोड तक ईएमयू गलियारों का विस्तार.

डीसी-एसी परिवर्तन:

- उपनगरीय रेलगाड़ी के चालन समय में बचत.
- एसी से डीसी लोको में और की तुलना में कोई परिवर्तन नहीं, अतः यात्रा समय में कमी.
- लंबी, तेज और भारी गाड़ियों को ढोना.

विद्युत ऊर्जा:

- डीसी/एसी रेकों की नई प्रौद्योगिकी में रिजनरेटिव ब्रेक लगाने की शुरुआत करने के कारण विद्युत ऊर्जा में 35% से अधिक की बचत.

मुंबई शहरी परिवहन परियोजना- एमयूटीपी चरण -II

एमयूटीपी–II को वर्ष 2008-09 के बजट के दौरान कुल ₹5,300 करोड़ की लागत पर स्वीकृत किया गया था. एमयूटीपी–II को विश्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से तथा शेष भाग 50:50 के आधार पर महाराष्ट्र सरकार और रेल मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया गया है। 430 मिलियन अमरीकी डालर (₹1910 करोड़) का ऋण विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत किया गया है और 23.07.2010 को विश्व बैंक के साथ समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं.

एमयूटीपी चरण-II में प्रमुख इनपुट :

- अतिरिक्त 88 रेलपथ किलोमीटर.
- 72 नए 12-कार रेक
- मध्य रेलवे में (172 रेलपथ किलोमीटर) पर डीसी से एसी में परिवर्तन से मुंबई उपनगरीय प्रणाली पर डीसी-एसी परिवर्तन कार्य पूरा हो गया.
- 2,839 परियोजना प्रभावित परिवारों का पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन

प्रमुख कार्यों की प्रगति:

- 72/12 कार ईएमयू रेकों (86 डिब्बे) की खरीद/विनिर्माण.
- अंधेरी से गोरेगांव तक हार्बर लाइन का विस्तार.
- ठाणे-दीवा के बीच 5वीं और छठी लाइनें.
- छत्रपति शिवाजी टर्मिनस-कुर्ला के बीच 5वीं और 6ठी लाइनें.
- मुंबई सेंट्रल-बोरीवली के बीच छठी लाइन का डीसी से एसी में परिवर्तन.

आगे का रास्ता - मुंबई शहरी परिवहन परियोजना-एमयूटीपी चरण - III :

अगले 20 वर्षों के लिए उपनगरीय यातायात की भावी आवश्यकता को पूरा करने के लिए मौजूदा एमयूटीपी- I तथा II पर्याप्त नहीं होंगीं इसलिए, मौजूदा उपनगरीय रेल अवसंरचना को बढ़ाने और मजबूत करने की और आवश्यकता है. उपनगरीय बुनियादी ढांचे की ऐसी वृद्धि और मजबूत करने के लिए पहचाने गए कार्यों को एक ही परियोजना में डाला जा सकता है जिसे एमयूटीपी-III के रूप में नामित किया जा सकता है. पहचाने गए प्रमुख गलियारे नीचे दिए अनुसार हैं:

- पनवेल-करजत दोहरीकरण.
- थाने-हार्बर लिंक (एरोली-कलवा)
- विरार-दहानू रोड तीसरी और चौथी लाइन.
- सीएसटीएम-पनवेल के बीच हार्बर लाइन पर तेज गति वाले गलियारे की व्यवस्था.
- विरार-वसई-दीवा-पनवेल खंड पर नई उपनगरीय लाइन.
- गोरेगांव से बोरीवली तक हार्बर लाइन का विस्तार.
- बोरीवली-विरार पाचंवीं तथा छठी लाइन.
- कल्याण-कसारा तीसरी तथा चौथी लाइन.
- कल्याण-करजत तीसरी तथा चौथी लाइन.

पलासधारी पर एमआरवीसी इएमयू गाड़ी का विहंगम दृश्य